



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मार्च 31, 2011/चैत्र 10, 1933

No. 177]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2011/CHAITRA 10, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2011

सं. 22/2011-सेवाकर

सा.का.नि. 280(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 तथा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात सेवाओं नियम, 2005 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित और नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्यात सेवाओं (द्वितीय संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2011 को प्रवृत्त होंगे।

2. निर्यात सेवाओं संशोधन नियम, 2005 में, नियम 3, अधिनियम (1), खण्ड (ii), द्वितीय परंतुक में "ययज" का लोप किया जायेगा।

[फा. सं. 334/3/2011-टीआरयू]

समर नंदा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. 11/2006-सेवाकर, तारीख 19 अप्रैल, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 227(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 13/2011-सेवाकर, तारीख 1 मार्च, 2011, सा.का.नि. 170(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2011

No. 22/2011-Service Tax

G.S.R. 280(E).— In exercise of the powers conferred by Sections 93 and 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Services Rules, 2005, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Services (Second Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2011.

2. In the Export of Services Rules, 2005, in rule 3, in sub-rule (1), in clause (ii), in the second proviso, the brackets and letters "(zzh)" shall be omitted.

[F.No. 334/1/2011-TRU]

SAMAR NANDA, Under Secy.

Note : The principal rules were notified vide notification No. 9/2005-Service Tax, dated the 3rd March, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 151(E), dated the 3rd March, 2005 and last amended vide notification No. 12/2011-Service Tax, dated the 1st March, 2011, vide number G.S.R 169(E), dated the 1st March, 2011.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2011

सं. 23/2011-सेवाकर

सा.का.नि. 281(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 66क के साथ पठित धारा 93 तथा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेवाओं का कराधान (भारत के बाहर उपलब्ध कराई गई और भारत में प्राप्त) नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित और नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेवाओं का कराधान (भारत के बाहर उपलब्ध कराई गई और भारत में प्राप्त) संशोधन नियम, 2011 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2011 को प्रवृत्त होंगे।

2. सेवाओं का कराधान (भारत के बाहर उपलब्ध कराई गई और भारत में प्राप्त) संशोधन नियम, 2006 में, नियम 3, खण्ड (ii), द्वितीय परंतुक में “ययज” का लोप किया जायेगा।

[फा. सं. 334/3/2011-टीआरयू]

समर नंदा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. 11/2006-सेवाकर, तारीख 19 अप्रैल, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 227(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 13/2011-सेवाकर, तारीख 1 मार्च, 2011, सा.का.नि. 170 (अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2011

No. 23/2011-Service Tax

G.S.R. 281(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 93 and 94 read with Section 66A of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Taxation of Services (Provided from Outside India and Received in India) Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Taxation of Services (Provided from Outside India and Received in India) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2011.

2. In the Taxation of Services (Provided from Outside India and Received in India) Rules, 2006, in rule 3, in clause (ii), in the second proviso, the brackets and letters “(zzh)” shall be omitted.

[F.No. 334/3/2011-TRU]

SAMAR NANDA, Under Secy.

Note : The principal rules were notified *vide* notification No. 11/2006-Service Tax, dated the 19th April, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 227(E), dated the 19th April, 2006 and last amended *vide* notification No. 13/2011-Service Tax, dated the 1st March, 2011, *vide* number G.S.R. 170(E), dated the 1st March, 2011.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2011

सं. 24/2011-सेवाकर

सा.का.नि. 282(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 के खण्ड (कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेवाओं का कराधान (मूल्य का निर्धारण) नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित और नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेवाओं का कराधान (मूल्य का निर्धारण) द्वितीय संशोधन नियम, 2011 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2011 को प्रवृत्त होंगे।

2. सेवाकर में (मूल्य का निर्धारण) संशोधन नियम, 2006, नियम 2ख में, शब्द “उस दिन के उस करेंसी के” के स्थान पर “उस समय के उस करेंसी के” को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[फा. सं. 334/3/2011-टीआरयू]

समर नंदा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. 12/2006-सेवाकर, तारीख 19 अप्रैल, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 228(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 02/2011-सेवाकर, तारीख 1 मार्च, 2011, सा.का.नि. 159 (अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2011

No. 24/2011-Service Tax

G.S.R. 282(E).—In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (2) of Section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax (Determination of Value) Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Service Tax (Determination of Value) Second Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2011.

2. In the Service Tax (Determination of Value) Rules, 2006, in rule 2B, for the words “reference rate for that currency for that day”, the words “reference rate for that currency at that time” shall be substituted.

[F.No. 334/3/2011-TRU]

SAMAR NANDA, Under Secy.

Note : The principal rules were notified *vide* notification No. 12/2006-Service Tax, dated the 19th April, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 228(E), dated the 19th April, 2006 and last amended *vide* notification No. 02/2011-Service Tax, dated the 1st March, 2011, *vide* number G.S.R. 159(E), dated the 1st March, 2011.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2011

सं. 25/2011-सेवा कर

सा.का.नि. 283(अ).—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) और खण्ड (जजज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कराधान बिन्दु नियमावली, 2011 को पुनः संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को कराधान बिन्दु संशोधन नियमावली, 2011 कहा जा सकता है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2011 को प्रवृत्त होंगे।

2. कराधान बिन्दु नियमावली, 2011 (एतदपश्चात् “उक्त नियमावली” के रूप में उल्लिखित) में नियम 3 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“3. कराधान बिन्दु का निर्धारण.—इन नियमों के उद्देश्यों के लिए जब तक अन्यथा प्रावधान न किया जाए “कराधान बिन्दु” निम्नलिखित होगा,—

(क) वह समय जब प्रदान की गई अथवा प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए बीजक जारी किया जाता है:

प्रावधान किया गया कि जहां सेवा प्रावधान के सम्पादन के बाद चौदह दिनों के अंदर बीजक जारी नहीं किया जाता है, कराधान बिन्दु ऐसे सम्पादन की तिथि होगा।

(ख) ऐसे मामले में जहां सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति खंड (क) में विनिर्दिष्ट समय से पूर्व भुगतान प्राप्त करता है वहां ऐसे भुगतान की सीमा तक ऐसे भुगतान को प्राप्त करने का समय।

स्पष्टीकरण:—इस नियम के उद्देश्य के लिए कराधेय सेवा के प्रावधान के लिए सेवा प्रदाता द्वारा जहां भी कोई अग्रिम किसी भी ज्ञात नाम से प्राप्त किया जाता है, कराधेय बिन्दु ऐसे प्रत्येक अग्रिम की प्राप्ति की तिथि होगा।”

3. उक्त नियमावली के नियम 4 में,—

(i) जहां भी “दर परिवर्तन” शब्द है वहां इन शब्दों की जगह “कर की प्रभावी दर में परिवर्तन” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) “कर की दर में परिवर्तन” अथवा कर दर में परिवर्तन” अथवा “कर दर का परिवर्तन” शब्द क्रमशः दोनों जगहों में जहां भी आए हैं, वहां “प्रभावी कर दर में परिवर्तन” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iii) खंड (ख) के उप-खंड (iii) के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण:—इस नियम के उद्देश्यों के लिए “कर की प्रभावी दर में परिवर्तन” में मूल्य के अंश, जिस पर वित्त अधिनियम, 1944 अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन जारी अधिसूचना के दृष्टिकोण से कर देय होता है, अधिसूचना में परिवर्तन शामिल है।”

4. उक्त नियमावली के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा यथा :—

“6 सेवा की सतत आपूर्ति के मामले कराधान के प्रारंभ बिन्दु :—नियम 3, 4 या 8 में निहित किसी भी बात के बावजूद सेवा की सतत आपूर्ति के मामले में कराधान का प्रारंभ

(क) उस समय से होगा जब प्रदान की गई या प्रदान किये जाने के लिए निश्चित की गई सेवा के लिए बीजक जारी कर दिया जाता है :

बशर्ते कि जहां बीजक को सेवा के प्रावधान को पूरा होने के 14 दिन के भीतर नहीं जारी किया जाता है तो कराधान का प्रारंभ बिन्दु वह तारीख होगी जिस दिन सेवा का प्रावधान पूरा हो गया है।

(ख) यदि उप-वाक्य (क) में विनिर्दिष्ट समय के पहले, सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति भुगतान प्राप्त कर लेता है तो, भुगतान की गई सीमा तक, सेवा के लिए यह माना जाएगा कि यह भुगतान के समय ही प्राप्त की गई है।”

स्पष्टीकरण 1 :—इस नियम के प्रयोजन के लिए जहां कि सेवा के सम्पूर्ण या उसके अंशतः प्रावधान का आवधिक निर्धारण अनुबंध की दृष्टि से किसी घटना के पूरा होने पर होता है, जिसके लिए यह जरूरी है कि सेवा प्राप्त करने वाला सेवा प्रदान करने वाले को कोई भुगतान करे, सेवा का प्रावधान तब पूरा माना जाएगा जब ऐसी कोई घटना पूरी हो जाती है जो अनुबंध में विनिर्दिष्ट हो।

स्पष्टीकरण 2 :—इस नियम के प्रयोजन के लिए, जहां कहीं भी कोई अग्रिम राशि, या इसे जिस नाम से भी जाना जाता हो, सेवा प्रदाता द्वारा कर योग्य सेवा के प्रयोजन के लिए प्राप्त कर ली जाती है तो कराधान का प्रारंभ बिन्दु वह समय माना जाएगा जिस तारीख को ऐसी अग्रिम राशि प्राप्त की गई हो।”

5. नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा यथा—

“7. विशिष्ट सेवाओं या व्यक्तियों के बारे में कराधान का प्रारंभ :—इन नियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद निम्नलिखित के मामले में कराधान का प्रारंभ बिन्दु वह तारीख होगी जिस दिन भुगतान प्राप्त किया जाता है या दिया जाता है, जैसी भी स्थिति हो।

(क) सेवायें, जो सेवा निर्यात नियमावली, 2005 के नियम 3, के उप-वाक्य (1) के दायरे में आती हैं।

(ख) व्यक्ति, जिनके लिए आवश्यक है कि वे वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 68(2) के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के मामले में इस बावत बनाये गये नियमों के अंतर्गत प्राप्तकर्ता के रूप में कर अदा करें।

(ग) व्यक्ति या स्वामित्व वाली फर्म या भागीदारी फर्म जो वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105) के उप-वाक्य (त), (थ), (ध), (न), (प), (यक), (ययययद) के अंतर्गत उल्लिखित कर योग्य सेवाओं को प्रदान करती हैं :

बशर्ते कि उप-वाक्य (क) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं के मामले में यदि भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निध रित अवधि के भीतर प्राप्त नहीं हो पाता है तो कराधान के प्रारंभ बिन्दु का निर्धारण इन नियमों के अंतर्गत इस प्रकार किया जायेगा कि मानो यह नियम अस्तित्व में ही नहीं है :

बशर्ते और भी कि उप-वाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं के मामलों में, यदि भुगतान बीजक की तारीख से 6 महीने के भीतर नहीं कर दिया जाता है तो इन नियमों के अंतर्गत कराधान के प्रारंभिक बिन्दु का निर्धारण यह मान कर किया जाएगा कि मानो यह नियम अस्तित्व में नहीं है :

बशर्ते और भी कि "संबद्ध उद्यमों" के मामले में जहां कि सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति भारत के बाहर है, तो कराधान का प्रारंभिक बिन्दु सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बही खाते में दर्ज क्रेडिट की तारीख के पहले या भुगतान की गई तारीख को होगा।"

6. नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

"9 संक्रांतिक प्रावधान.—इस उप-नियम में निहित किसी भी बात का निम्न पर प्रभाव नहीं पड़ेगा :—

- (i) जहां इस सेवा के प्रावधान इस नियम के लागू होने की तारीख से पहले पूरा हो जाते हैं
- (ii) जहां बीजक इन नियमों के लागू होने की तारीख के पहले जारी हो जाता है।

परन्तु उन सेवाओं के लिए जिनके लिए प्रावधान को 30 जून, 2011 के पहले पूरा कर लिया गया है और किसी भी बीजक के लिए जो कि 30 जून, 2011 के पहले जारी हो गये हैं, कर दाता के विकल्प पर, कराधान का प्रारंभ बिन्दु वह तारीख होगी जिस तारीख को भुगतान प्राप्त किया गया है या किया गया है, जैसी भी स्थिति हो।"

[फा. सं. 334/3/2011-टी. आर. यू.]

समर नन्दा, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना सं. 18/2011-सेवा कर, दिनांक 1 मार्च, 2011 को सा.का.नि. 175(अ), दिनांक 1 मार्च, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2011

No. 25/2011-Service Tax

G.S.R. 283(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) and clause (hhh) of sub-section (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Point of Taxation Rules, 2011, namely :—

1. (1) These rules may be called the Point of Taxation (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2011.

2. In the Point of Taxation Rules, 2011 (hereinafter referred to as the "said rules"), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :—

"3. Determination of point of taxation.— For the purposes of these rules, unless otherwise provided, 'point of taxation' shall be,—

(a) the time when the invoice for the service provided or to be provided is issued:

Provided that where the invoice is not issued within fourteen days of the completion of the provision of the service, the point of taxation shall be date of such completion.

(b) in a case, where the person providing the service, receives a payment before the time specified in clause (a), the time, when he receives such payment, to the extent of such payment.

Explanation .— For the purpose of this rule, wherever any advance by whatever name known, is received by the service provider towards the provision of taxable service, the point of taxation shall be the date of receipt of each such advance."

3. In rule 4 of the said rules,—

- (i) for the words "change of rate", wherever they occur, the words "change in effective rate of tax" shall be substituted;
- (ii) for the words "change of rate of tax" or "change in tax rate" or "change of tax rate", respectively at both the places where they occur, the words "change in effective rate of tax" shall be substituted;
- (iii) after sub-clause (iii) of clause (b), the following Explanation shall be inserted, namely :—

"Explanation.—For the purposes of this rule, "change in effective rate of tax" shall include a change in the portion of value on which tax is payable in terms of a notification issued under the provisions

of Finance Act, 1994 or rules made thereunder."

4. For rule 6 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"6. Determination of point of taxation in case of continuous supply of service.—Notwithstanding anything contained in rules 3, 4, or 8, in case of continuous supply of service, the 'point of taxation' shall be,—

(a) the time when the invoice for the service provided or to be provided is issued :

Provided that where the invoice is not issued within fourteen days of the completion of the provision of the service, the point of taxation shall be date of such completion.

(b) in a case, where the person providing the service, receives a payment before the time specified in clause (a), the time, when he receives such payment, to the extent of such payment.

Explanation 1.—For the purpose of this rule, where the provision of the whole or part of the service is determined periodically on the completion of an event in terms of a contract, which requires the service receiver to make any payment to service provider, the date of completion of each such event as specified in the contract shall be deemed to be the date of completion of provision of service.

Explanation 2.—For the purpose of this rule, wherever any advance, by whatever name known, is received by the service provider towards the provision of taxable service, the point of taxation shall be the date of receipt of each such advance."

5. For rule 7, the following rule shall be substituted, namely:—

"7. Determination of point of taxation in case of specified services or persons.—Notwithstanding anything contained in these rules, the point of taxation in respect of,—

(a) the services covered by sub-rule (1) of rule 3 of Export of Services Rules, 2005;

(b) the persons required to pay tax as recipients under the rules made in this regard in respect of services notified under sub-section (2) of section 68 of the Finance Act, 1994;

(c) individuals or proprietary firms or partnership firms providing taxable services referred to in sub-clauses (p), (q), (s), (t), (u), (za), (zzzzm) of clause (105) of Section 65 of the Finance Act, 1994,

shall be the date on which payment is received or made, as the case may be :

Provided that in case of services referred to in clause (a), where payment is not received within the period specified by the Reserve Bank of India, the point of

taxation shall be determined, as if this rule does not exist :

Provided further that in case of services referred to in clause (b) where the payment is not made within a period of six months of the date of invoice, the point of taxation shall be determined as if this rule does not exist :

Provided also that in case of "associated enterprises", where the person providing the service is located outside India, the point of taxation shall be the date of credit in the books of account of the person receiving the service or date of making the payment whichever is earlier.

6. For rule 9, the following rule shall be substituted, namely:—

"9. Transitional Provisions.—Nothing contained in this sub-rule shall be applicable,—

- (i) where the provision of service is completed; or
- (ii) where invoices are issued prior to the date on which these rules come into force :

Provided that services for which provision is completed on or before 30th day of June, 2011 or where the invoices are issued up to the 30th day of June, 2011, the point of taxation shall, at the option of the taxpayer, be the date on which the payment is received or made as the case may be."

[F.No. 334/3/2011 - TRU]

SAMAR NANDA, Under Secy.

Note :—The principal notification No. 18/2011-Service Tax, dated the 1st March 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.175(E), dated the 1st March, 2011.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2011

सं. 26/2011-सेवा कर

सा.का.नि. 284(अ).—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा सेवा कर नियमावली, 1994 को पुनः संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को सेवा-कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011 कहा जा सकता है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2011 को प्रवृत्त होंगे।

2. सेवा कर नियमावली, 1994 (एतद्वारा "उक्त नियमावली" के रूप में उल्लिखित) में नियम 4(क) में उप-नियम (1) में,—

(i) "का प्रावधान" शब्दों की जगह "का सम्पादन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(ii) द्वितीय परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

11834 7/11-2

“यह भी प्रावधान किया गया कि सेवा की निरंतर आपूर्ति के मामले में ऐसी कराधेय सेवा प्रदान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध में विनिर्दिष्ट प्रत्येक घटना, जिसके लिए सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा सेवा प्रदाता को कोई भुगतान करना अपेक्षित है, के सम्पादन के बाद 14 दिनों के अंदर बीजक, बिल अथवा चालान, जैसा मामला हो, जारी करेगा”।

3. उक्त नियमावली के नियम 6 में,—

(i) “आंशिक रूप से किसी कारणवश” शब्दों के बाद “अथवा सेवा के प्रावधान में कमी अथवा अनुबंध में अंतर्विष्ट किसी शर्त के कारण यदि बीजक राशि पर पुनःवार्ता की जाती है” शब्द जोड़े जाएंगे।

(ii) खण्ड (क) की जगह निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(क) जिस व्यक्ति से भुगतान प्राप्त हुआ उसे दी गई सेवा के लिए उस पर प्राप्त भुगतान अथवा उसके अंश को वापस कर दिया है”; अथवा

(ख) उप-नियम (7ख) में,—

(i) “विनिमय की मुद्रा की कुल राशि के 0.1 प्रतिशत की दर से” शब्दों एवं आंकड़ों की जगह निम्नलिखित “दर से शब्द” प्रतिस्थापित किए जाएंगे,—

(ii) “अधिनियम के” शब्दों की जगह, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“अधिनियम के अर्थात् :—

(क) 25 रुपए की न्यूनतम राशि के अंतर्गत 100,000 रुपए तक की राशि के लिए विनिमय की मुद्रा की कुल राशि का 0.1 प्रतिशत; और

(ख) 100 रुपए और 100,000 रुपए से अधिक एवं 10,00,000 रुपए तक की राशि के लिए विनिमय की मुद्रा की कुल राशि का 0.05 प्रतिशत; और

(ग) 550 रुपए तथा 5000 रुपए तक की अधिकतम राशि के अंतर्गत 10,00,000 रुपए से अधिक राशि के लिए विनिमय की मुद्रा की कुल राशि का 0.01 प्रतिशत प्रावधान किया गया कि सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति वित्त वर्ष के लिए ऐसा विकल्प देगा और ऐसा विकल्प उस वित्त वर्ष के शेष भाग के दौरान वापस नहीं लिया जाएगा।”

[फा. सं. 334/3/2011-टीआरयू]

समर नन्दा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियमावली सा.का.नि. 546(अ) दिनांक 28 जून, 1994 के जरिए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. 2/1994-सेवा-कर, दिनांक 28 जून, 1994 के द्वारा अधिसूचित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन सं. सा.का.नि. 160(अ), दिनांक 1 मार्च, 2011 के जरिए अधिसूचना सं. 3/2011-सेवा-कर, दिनांक 1 मार्च, 2011 के द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2011

No. 26/2011-Service Tax

G.S.R. 284(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of Section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax Rules, 1994, namely :—

1. (1) These rules may be called the Service Tax (Second Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2011.

2. In the Service Tax Rules, 1994 (hereinafter referred to as the “said rules”), in rule (4A), in sub-rule (1),—

(i) for the words “provision of”, the words “completion of” shall be substituted;

(ii) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided also that in case of continuous supply of service, every person providing such taxable service shall issue an invoice, bill or challan, as the case may be, within fourteen days of the date when each event specified in the contract, which requires the service receiver to make any payment to service provider, is completed.”;

3. In rule 6 of the said rules,—

(a) in sub-rule (3),—

(i) after the words “partially for any reason”, the words “or where the amount of invoice is renegotiated due to deficient provision of service; or any terms contained in a contract,” shall be inserted;

(ii) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

“(a) has refunded the payment or part thereof, so received for the service provided to the person from whom it was received; or”

(b) in sub-rule (7B),—

(i) for the words and figures “at the rate of 0.1 per cent. of the gross amount of currency exchanged”, the words “at the following rate” shall be substituted;

(ii) for the words “of the Act”, the following shall be substituted, namely :—

“of the Act, namely :—

(a) 0.1 per cent. of the gross amount of currency exchanged for an amount up to rupees 100,000, subject to the minimum amount of rupees 25; and

(b) rupees 100 and 0.05 per cent. of the gross amount of currency exchanged for an amount of rupees exceeding rupees 100,000 and up to rupees 10,00,000; and

- (c) rupees 550 and 0.01 per cent. of the gross amount of currency exchanged for an amount of rupees exceeding 10,00,000, subject to maximum amount of rupees 5000 :

Provided that the person providing the service shall exercise such option for a financial year and such option shall not be withdrawn during the remaining part of that financial year."

[F.No. 334/3/2011-TRU]

SAMAR NANDA, Under Secy.

Note.—The principal rules were notified *vide* notification No. 2/1994-Service Tax, dated the 28th June, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 546(E), dated the 28th June, 1994 and last amended *vide* notification No.3/2011-Service Tax, dated the 1st March, 2011, *vide* number G.S.R. 160(E), dated the 1st March, 2011.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2011

सं. 27/2011-सेवा-कर

सा.का.नि. 285(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् वित्त अधिनियम भी कहा गया है) की धारा 93 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 19/2009-सेवाकर, तारीख 7 जुलाई, 2009, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, सा.का.नि. 491(अ), तारीख 7 जुलाई, 2009 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, शब्द 'किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा एक अनुसूचित बैंक', के स्थान पर शब्द 'किसी भी बैंक, तथा भारत से बाहर स्थित बैंक, या मुद्रा परिवर्तक सहित किसी भी अन्य बैंक या मुद्रा परिवर्तक' प्रतिस्थापित किया जायेगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2011 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/3/2011-टीआरयू]

समर नंदा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना 19/2009-सेवा-कर, तारीख 7 जुलाई, 2009, सा.का.नि. 491(अ), तारीख 7 जुलाई, 2009 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, 31st March, 2011

No. 27/2011-Service Tax

G.S.R. 285 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification

of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 19/2009-Service Tax, dated the 7th July, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 491 (E), dated the 7th July, 2009, for the words "a Scheduled bank," by any other Scheduled bank", the words "any bank, including a bank located outside India, or money changer, by any other bank or money changer" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2011.

[F.No. 334/3/2011-TRU]

SAMAR NANDA, Under Secy.

Note.— The principal notification No. 19/2009-Service Tax, dated the 7th July, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 491 (E), dated the 7th July, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2011

सं. 13/2011-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 286(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा:—

1. (क) इन नियमों को सेनवेट क्रेडिट (तीसरा संशोधन) नियमावली, 2011 कहा जायेगा।

(ख) ये 1 अप्रैल, 2011 से प्रवर्तित होंगे।

2. नियम 4 में उप-नियम 7 और उप-नियम 7 के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:—

"(7) आदान सेवा की बाबत सेनवेट क्रेडिट उस दिन या उस दिन के पश्चात् अनुमल होगी जिन दिन बीजक, बिल या जैसी भी स्थिति हो, चालान, जो नियम 9 में संदर्भित हो, प्राप्त हो जाता है :

बशर्ते कि आदान सेवा के मामले में जब सेवा का प्राप्तकर्ता 'रिवर्स चार्ज' पर सेवा-कर का भुगतान करता है तो ऐसी आदान सेवा के मामले में सेनवेट क्रेडिट की अनुमति उस दिन से या उस दिन के बाद से होगी जिस दिन आदान सेवा के मूल्य का भुगतान किया जाता है और भुगतान किये गये या भुगतान किये जाने योग्य सेवा-कर को बीजक, बिल या जैसी भी स्थिति हो, चालान, जो कि नियम 9 में संदर्भित हो, में इंगित किया गया हो :

बशर्ते और भी कि यदि बीजक, बिल या जैसी भी स्थिति हो, चालान जो नियम 9 में संदर्भित है, में निर्दिष्ट आदान सेवा के मूल्य और सेवा-कर भुगतान किया गया या भुगतान योग्य का भुगतान बीजक की तारीख के तीन महीने के भीतर नहीं कर दिया जाता है तो विनिर्माता या सेवा प्रदाता जिसने कि ऐसी सेवा पर क्रेडिट प्राप्त की है, ऐसे अदा

क्रेडिट पर प्राप्त सेनवेट क्रेडिट के बराबर की राशि का भुगतान करेगा और जब उक्त भुगतान किया जाता है तो उत्पादक अथवा उत्पाद सेवा प्रदाता, जैसा मामला हो, इन नियमों के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत पूर्व में भुगतान किए गए सेनवेट क्रेडिट के समतुल्य राशि का क्रेडिट लेने का पात्र होगा :

यह भी प्रावधान किया गया कि निविष्ट सेवा के किए गए किसी भुगतान अथवा आंशिक भुगतान को वापस किया जाता है अथवा ऐसी निविष्ट सेवा क्रेडिट लेने वाले उत्पादक अथवा सेवा प्रदाता द्वारा क्रेडिट नोट प्राप्त किया जाता है तो वह इस प्रकार वापस की गई अथवा क्रेडिट की गई राशि के संबंध में लिए गए सेनवेट क्रेडिट के समतुल्य राशि का भुगतान करेगा ।

यह भी प्रावधान किया गया कि दिनांक 1-4-2011 से पूर्व जारी नियम 9 में उल्लिखित बीजक, बिल अथवा जैसा मामला हो, चालान, के संबंध में सेनवेट क्रेडिट की अनुमति, निविष्ट सेवा के मूल्य के भुगतान और नियम 9 में उल्लिखित बीजक, बिल अथवा जैसा मामला हो, चालान, में यथा उल्लिखित भुगतान किए गए अथवा देय सेवा कर की तिथि को अथवा उस के बाद होगी ।”

स्पष्टीकरण I.—इस उप-नियम में वर्णित रकम, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, माल के विनिर्माता या निर्गम सेवा के प्रदाता द्वारा आगामी मास की पांच तारीख को या उससे पूर्व, मार्च मास के सिवाय जब ऐसा संदाय मार्च मास की 31 तारीख को या उससे पूर्व किया जाएगा, सेनवेट प्रत्यय या अन्यथा विकलित करते हुए संदत्त की जाएगी ।

स्पष्टीकरण II.—यदि माल का विनिर्माता या निर्गम सेवा का प्रदाता इस उप-नियम के अधीन संदेय रकम को संदाय करने में असफल रहता है तो उससे, गलत रूप से सेनवेट प्रत्यय की वसूली के लिए नियम 14 में यथाउपबोधित रीति से वसूल किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण III.—यदि कोई विनिर्माता जो किसी वित्तीय वर्ष में निकासी के मूल्य पर आधारित किसी अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त करता है और कोई सेवा प्रदाता जो कोई व्यक्ति, सांपत्तिक फर्म या भागीदारी फर्म है तो उप-नियम (7) में आने वाले “आगामी मास” और “मार्च मास” पदों को क्रमशः “आगामी तिमाही” और “मार्च मास को समाप्त होने वाली तिमाही” पढ़ा जाएगा” ।

3. उक्त नियमावली के नियम 6 में, स्पष्टीकरण 1 में खंड (ग) के पश्चात “व्यापारकृत माल के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अंतर होगा” शब्दों के स्थान पर “बेचे गये माल के विक्रय मूल्य और लागत के बीच का अंतर या बेचे गये माल की लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होगा (बेचे गये माल की लागत का आकलन समान्यतया लेखा प्रणाली के सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा और इसमें इसकी खरीद पर किये जाने वाले खर्च को शामिल नहीं किया जायेगा)” शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

4. नियम 9 में खण्ड (ख) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थातः—

“(खख) ऐसे मामले जिनमें सेवा-कर के भुगतान से बचाने के लिए धोखा अथवा साठ गांठ अथवा जानबूझकर गलत बयानी अथवा तथ्यों के छिपाव अथवा वित्त अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान के उल्लंघन द्वारा गैर-उद्ग्रहण अथवा गैर-भुगतान अथवा अल्प उद्ग्रहण अथवा अल्प भुगतान के कारण सेवा प्रदाता से अतिरिक्त कर राशि वसूली योग्य हो जाती है, को छोड़कर सेवा-कर नियमावली, 1994 के प्रावधानों के दृष्टिकोण से उत्पाद सेवा प्रदाता द्वारा जारी अनुपूरक बीजक, बिल अथवा चालान ।”

[फा सं. 334/3/2011-टीआरयू]

समर नंदा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियमावली भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), तारीख 10 सितम्बर, 2004 में अधिसूचना सं. 23/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (नै.टै.), तारीख 10 सितम्बर, 2004, सा.का.नि. 600 (अं), तारीख 10 सितम्बर, 2004 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 9/2011-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (नै.टै.), तारीख 24 मार्च, 2011 सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 24 मार्च, 2011 के द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2011

No. 13/2011-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 286(E).—In exercise of the powers conferred by Section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and Section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely :—

1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (Third Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2011.

2. In the CENVAT Credit Rules, 2004 (hereinafter referred to as the “said rules”) in rule 4, for sub-rule 7, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(7) The CENVAT credit in respect of input service shall be allowed, on or after the day on which the invoice, bill or, as the case may be, challan referred to in rule 9 is received :

Provided that in case of an input service where the service tax is paid on reverse charge by the recipient of the service, the CENVAT credit in respect of such input service shall be allowed on or after the day on which payment is made of the value of input service and the service tax paid or payable as indicated in invoice, bill or, as the case may be, challan referred to in rule 9 :

Provided further that in case the payment of the value of input service and the service tax paid or payable as indicated in the invoice, bill or, as the case may be, challan referred to in rule 9, is not made within three months of the date of the invoice, bill or, as the case may be, challan, the manufacturer or the service provider who has taken credit on such input service, shall pay an amount equal to the CENVAT credit availed on such input service and in case the said payment is made, the manufacturer or output service provider, as the case may be, shall be entitled to take the credit of the amount equivalent to the CENVAT credit paid earlier subject to the other provisions of these rules :

Provided also that if any payment or part thereof, made towards an input service is refunded or a credit note is received by the manufacturer or the service provider who has taken credit on such input service, he shall pay an amount equal to the CENVAT credit availed in respect of the amount so refunded or credited :

Provided also that CENVAT credit in respect of an invoice, bill or, as the case may be, challan referred to in rule 9, issued before the 1st day of April, 2011 shall be allowed, on or after the day on which payment is made of the value of input service and the service tax paid or payable as indicated in invoice, bill or, as the case may be, challan referred to in rule 9.

Explanation I.—The amount mentioned in this sub-rule, unless specified otherwise, shall be paid by the manufacturer of goods or the provider of output service by debiting the CENVAT credit or otherwise on or before the 5th day of the following month except for the month of March, when such payment shall be made on or before the 31st day of the month of March.

Explanation II.—If the manufacturer of goods or the provider of output service fails to pay the amount payable under this sub-rule, it shall be recovered, in the manner as provided in rule 14, for recovery of CENVAT credit wrongly taken.

Explanation III.—In case of a manufacturer who avails the exemption under a notification based on the value of clearances in a financial year and a service provider who is an individual or proprietary firm or partnership firm, the expressions, "following month" and "month of March" occurring in sub-rule (7) shall be read respectively as "following quarter" and "quarter ending with the month of March".

3. In rule 6 of the said rules, in Explanation I, in clause (c) for the words "shall be the difference between the sale price and the purchase price of the goods traded", the words "shall be the difference between the sale price and the cost of goods sold (determined as per the generally accepted accounting principles without including the

expenses incurred towards their purchase) or ten per cent. of the cost of goods sold, whichever is more" shall be substituted.

4. In rule 9 of the said rules, after clause (b), the following clause may be inserted, namely :—

"(bb) a supplementary invoice, bill or challan issued by a provider of output service, in terms of the provisions of Service Tax Rules, 1994 except where the additional amount of tax became recoverable from the provider of service on account of non-levy or non-payment or short-levy or short-payment by reason of fraud or collusion or wilful mis-statement or suppression of facts or contravention of any of the provisions of the Finance Act or of the rules made thereunder with the intent to evade payment of service tax."

[F.No.334/3/2011-TRU]

SAMAR NANDA, Under Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 10th September, 2004, *vide* notification No. 23/2004-Central Excise (N.T.), dated the 10th September 2004, [G.S.R. 600(E), dated the 10th September, 2004] and last amended *vide* notification No. 9/2011-Central Excise (N.T.), dated 24th March, 2011 [G.S.R. 245(E), dated the 24th March, 2011].

CORRIGENDUM

New Delhi, the 31st March, 2011

G.S.R. 287(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 30/2011-Customs dated the 4th March, 2011 published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 188(E), dated the 4th March, 2011, for

"*Explanation.*—For the purpose of this Table, "Glass fibre" means glass fibre and articles thereof, including glass roving, glass chopped strands, glass chopped strands mats but excluding glass wool, glass yarn, glass woven fabrics and chopped strands of a kind generally treated with polyurethane or acrylic emulsion meant for thermoplastic applications, micro glass fibre used in battery separator, surface mat or surface veil or tissue."

read

"*Explanation.*—For the purpose of this Table, "Glass fibre" means glass fibre, including glass roving [assembled rovings (AR), direct rovings (DR)], glass chopped strands (CS), glass chopped strands mats (CSM). Specifically excluded from the scope of the product under consideration are glass wool, fibre glass wool, fibre glass insulation in wool form, glass yarn, glass woven fabrics, glass fibre fabric, glass woven rovings and chopped strands meant for thermoplastic applications, micro glass fibre used in battery separator, surface mat/surface veil/tissue."

[F.No.354/95/2010-TRU]

SANJEEV KUMAR SINGH, Under Secy.